साप्ताहिक

# बुलंद गोंदिया

खबरों का आईना

प्रधान संपादक : **अभिषेक चौहान** । संपादक : **नवीन अग्रवाल**

E-mail : **bulandgondia@gmail.com** | E-paper : **bulandgondia.net** | Office Contact No.: **7670079009** | R. No.: **MAH-HIN-10169**

वर्ष : 2 | अंक : 46 | गोंदिया : गुरुवार, 23 से 29 जुन 2022 | पृष्ठ : 4 | मूल्य : रु. 5


# तालाब गहरीकरण के नाम पर गौण खनिज का अवैध उत्खनन

## गोंदिया जिले के देवरी तहसील में पत्थरों का उत्खनन व गोरेगांव तहसील में मुरुम की खुदाई

बुलंद संवाददाता देवरी/गोरेगांव - गोंदिया जिले में गौण खनिज का अवैध उत्खनन बड़े पैमाने पर हो रहा है। कभी खेत तालाब के गहरीकरण व निर्माण के नाम पर तो कभी बिना लीज के किसानों की भूमि से गौण खनिज माफियाओं द्वारा बड़े पैमाने पर खनिज का अवैध रुप से उत्खनन कर शासन को लाखों रुपए के राजस्व का चुना लगाया जा रहा है। जिले में हाल ही में 2 मामले सामने आए हैं जिसमें देवरी तहसील में कृषि तालाब के गहराईकरण के नाम पर गिट्टी, बोल्डर व गोरेगांव में मुरुम का अवैध उत्खनन शासन की नाक के नीचे जोरों से चल रहा है।

गौरतलब है कि गौण खनिज का अवैध उत्खनन कर खनन माफिया प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए की राशि कमाने के साथ ही शासन के राजस्व को चूना लगा रहे हैं। पहला मामला देवरी तहसील कृषि तालाब की गहराईकरण व निर्माण के नाम पर बड़े पैमाने पर गिट्टी, बोल्डर व मुरुम का अवैध उत्खनन जोरो से शुरु है। जिसमें देवरी शहर से 10 किलोमीटर की दूरी पर सिरपुरबांध परिसर में इसी प्रकार का अवैध उत्खनन शुरु होने का मामला सामने आया है। जिसमें अनेक महीनों से यहां पर गिट्टी, बोल्डर का अवैध उत्खनन कर गिट्टी क्रेशर व खेत मालिक द्वारा राजस्व विभाग की आंखों में धूल झोंक कर करोडो रुपए के राजस्व को चूना लगाया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा कृषि तालाब का निर्माण व गहरीकरण करने के लिए मिट्टी व पत्थर का उत्खनन करने कुछ शर्तो व नियमों के तहत किसानों को मंजूरी दी जाती है। शासन की इस सुविधा का लाभ कुछ किसान व क्रेशर मालकों द्वारा अनाधिकृत रुप से लिया जा रहा है। जिसके तहत सिरपुर बांध में किसान की भूमि से अनेक महीनों से अवैध उत्खनन कर करोड़ों रुपए की गिट्टी व बोल्डर निकालकर क्रेशर में उपयोग किया जा रहा है। साथ ही जमीन से पत्थर निकालने के लिए भूमिगत बारुदी सुरंग का भी उपयोग किया जा रहा है। विशेष यह है कि उपरोक्त तहसील नक्षलग्रस्त होने से इस प्रकार जमीन में बारुद नहीं लगाया जा सकता। किंतु शासन के नियमों की अनदेखी कर बड़े पैमाने पर बारुदी सुरंग लगाकर गिट्टी का उत्खनन कर करोड़ों रुपए का लाभ क्रेशर मालिक द्वारा कमाया जा रहा है। उपरोक्त क्रेशरमशीन मुरदोली में अग्रवाल कंस्ट्रक्शन कंपनी की बताई जा रही है।

### राजस्व विभाग की रहस्यमयचुप्पी

देवरी तहसील में कृषि तालाब के नाम पर बड़े पैमाने पर अवैध उत्खनन किया जा रहा है, जो अनेक महीनों से निरंतर चल रहा है। किंतु राजस्व विभाग की चुप्पी रहस्यमय बनी हुई है। क्या सिरपुर बांध के पटवारी नींद में है? ऐसा प्रश्न परिसर के ग्रामीणों द्वारा शासन से किया जा रहा है। तहसील में शुरु अवैध उत्खनन को कौन अभय दे रहा है तथा इस संदर्भ में संबंधित किसान व क्रेशर मालक पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ग्रामीणों द्वारा मांग की जा रही है कि उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए।

गोरेगांव तहसील के ग्राम घोटी में तहसील कार्यालय के समीप तालाब

परिसर में कुछ गौण खनिज माफियाओं द्वारा जबरन अवैध रुम का उत्खनन कर दिन में ही वाहनों का परिवहन कर बिक्री की जा रही है। किन्तु प्रशासन द्वारा इस ओर अनदेखी की जा रही है। इस संदर्भ में घोटी के उपसरपंच संदीप मेश्राम द्वारा तहसीलदार गोरेगाव, जिलाधिकारी गोंदिया, उपविभागीय अधिकारी तिरोड़ा, खंडविकास अधिकारी पंचायत समिति गोरेगांव व पुलिस निरीक्षक पुलिस स्टेशन गोरेगांव में निवेदन भी दिया है। विशेय यह है कि उपरोक्त खनन के क्षेत्र में सभी शासकीय कार्यालय है, किंतु इस अवैध उत्खनन की ओर कोई भी कर्मचारी व अधिकारी द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस अवैध उत्खनन की जानकारी ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों तथा सदस्यों द्वारा पटवारी कार्यालय में दिए जाने के बावजूद भी इस और दुर्लक्ष किया जा रहा है। साथ ही मुरुम का उत्खनन कर परिवहन संबंधित मंजूरी ग्राम पंचायत से ना लेकर शासन के नियमों को भी उत्खनन माफियाओं द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है।

विशेष यह है कि उपरोक्त क्षेत्र में अवैध उत्खनन के दौरान उपसरपंच संदीप मेश्राम द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर देखा गया तो वहां पर करीब 20 ट्रैक्टर व दो जेसीबी मशीन के द्वारा अवैध उत्खनन किया जा रहा है। वर्तमान में करीब लाखों रुपए का मुरुम का उत्खनन किया जा चुका है। जिसका शासन को राजस्व भी नहीं पटाया गया है तथा इस मामले में राजस्व विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों की भी सांठगांठ होने तथा उन्हें इस अवैध उत्खनन से अवैध कमाई होने की भी बात सामने आ रही है। इस संदर्भ में ग्राम पंचायत के पदाधिकारी व ग्रामीणों द्वारा तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है।

# योग है जीवन जीने का सही तरीका

## राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी

मुंबई - राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने यहां कहा कि योग सिर्फ एक शारीरिक आसन नहीं है, बल्कि जीवन का एक आदर्श तरीका है जो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य प्रदान करता है।

राज्यपाल विदेश मंत्रालय के संभागीय कार्यालय द्वारा राजभवन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में बोल रहे थे। राजभवन के दरबार हॉल में आयोजित योग दिवस कार्यक्रम में 30 देशों के राजनीतिक और व्यापार प्रतिनिधियों के साथ-साथ भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद से छात्रवृत्ति पर भारत में अध्ययन करने वाले विभिन्न देशों के छात्रों ने भाग लिया। राज्यपाल ने विभिन्न देशों के वाणिज्य दूतों के साथ बातचीत की और उपस्थित गाइडों को सम्मानित किया। इस बार फिटनेस गुरु मिकी मेहता के मार्गदर्शन में योग किया गया। संभागीय पासपोर्ट अधिकारी राजेश गावंडे ने दर्शकों का स्वागत किया। आर्किटेक्ट अनुजा सावंत के वास्तु शास्त्र, डॉ श्वेता भाटिया के डाइटरी फैट और त्वचा विशेषज्ञ डॉ. श्रुति बर्दे ने इन्वेस्टिंग फॉर नेचुरल स्किन पर बात की। संगीतमय बाजीगरी के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। इस कार्यक्रम में ICCR की डिविजनल डायरेक्टर रेणु पृथ्यानी भी मौजूद थीं। इस दौरान द योग इंस्टीट्यूट के मार्गदर्शन में राजभवन के पदाधिकारियों व कर्मचारियों ने योग भी किया।

# लापरवाह चालकों पर पुलिस की कारवाई

### शहर थाने में 6 पर मामला दर्ज

बुलंद गोंदिया - जिले के दवनीवाडा थाना अंतर्गत महालगांव में हुई भीषण सडक दुर्घटना के बाद पुलिस विभाग द्वारा लापरवाह चालकों पर लगातार कारवाई की जा रही है। पुलिसकर्मियों को शहर के मुख्य मार्ग व चौराहों पर तैनात किया गया है। बुधवार 22 जून की सुबह 10 बजे के दौरान शहर के आंबेडकर चौक तथा बायपास मार्ग के राजाभोज चौक पर लापरवाह 6 चालकों पर कारवाई कर पुलिस ने मामला दर्ज किया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बायपास मार्ग के राजाभोज चौक पर दुपहिया क्रमांक एमएच-35 एन-1163 का चालक मोरवाही निवासी आरोपी रामदास आत्माराम डोये (39), दुपहिया क्रमांक एमएच-35 टी-3685 का चालक करंजी निवासी आरोपी गणेश उरकुडा वाढई (34), दुपहिया क्रमांक एमएच-35 एएन-8621 का चालक आडकुटोला निवासी आरोपी राजेश रुमणलाल रहांगडाले (32) के खिलाफ शिकायतों के आधार पर गोंदिया शहर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। उसी तरह शहर के आंबेडकर चौक पर दुपहिया क्रमांक एमएच-35 वाय-1017 का चालक मामा चौक निवासी विशाल भोसकर (32) व दुपहिया क्रमांक एमएच-20 बीएच-0511 का चालक परभनी निवासी आरोपी शशांक कावडे (22) के खिलाफ भादंवि की धारा 279 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आगे की जांच पुलिस कर रही है।

### अंगदान के लिए जनजागृति जन आंदोलन होना चाहिए
### स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे

मुंबई - अंगदान के लिए एक जन आंदोलन होना चाहिए। हमें इसके लिए जागरुकता पैदा करने की जरुरत है, ऐसा सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा। दोस्त फाउंडेशन की ओर से अंगदान दिंडी व चित्ररथ का आयोजन किया गया जिसकी टोपे ने झंडा लहराकर शुरुआत की। इस अवसर पर दोस्त फाउंडेशनके डॉ. कैलाश जावड़े, डॉ. वैशाली जावड़े, डॉ. गोविंद जावड़े, डॉ. स्वाति माने, विजय कोहड़ आदि उपस्थित थे। श्री टोपे ने कहा कि हमारे देश में कई नागरिकों को प्रत्यारोपण के लिए अलग-अलग अंगों की जरुरत है, लेकिन पर्याप्त अंग उपलब्ध नहीं हैं। कई नागरिकों को अंग नहीं मिलते हैं। इसलिए अंगदान के प्रति समाज में जागरुकता पैदा करने की जरुरत है। इसके लिए दोस्त फाउंडेशन की ओर से की जा रही जागरुकता महत्त्वपूर्ण है। अंगदान की जानकारी देते चित्ररथ में संत ज्ञानेश्वर महाराज और संत तुकाराम महाराज की पालकी समारोह में शामिल होंगी। इससे अंगदान को लेकर फैली भ्रांतियां दूर होंगी और समाज में सकारात्मक सोच पैदा होगी ऐसा डॉ. जावड़े ने कहा।

# जंगली सूअरों के हमले में चार घायल

## शहर के मोक्षधाम परिसर में हमले से बढा खतरा

बुलंद गोंदिया - जिले में दो अलग-अलग जगहों पर जंगली सूअर के हमले में चार घायल हो जाने की घटना सोमवार 20 जून की सुबह 7 बजे के दौरान सामने आयी है। सडक अर्जुनी तहसील के ग्राम मालीजुंगा खेत परिसर मार्ग पर दो और शहर के मोक्षधाम परिसर के डंम्पिंगयार्ड में सोनजारी परिवार के दो इस तरह कुल चार लोग जंगली सूअर के हमले में बूरी तरह घायल हो चुके है। घायलों के नाम सुभाष सेवालाल परतेती (31), प्रमोद नारायण परतेमी (32) दोनों मालीजुंगा निवासी तथा मोक्षधाम के डम्पिंगयार्ड में घटी घटना में राजकुमार बहेगू नेताम (48) व चंदाबाई विक्रम बेहरे (28) दोनो गौतमनगर निवासी बताए गए है। घायलों को उपचार के लिए जिला केटीएस अस्पताल में भर्ती किया गया है। घटना की जानकारी वनविभाग को दे दी गई है।

मोक्षधाम परिसर में जंगली सूअरों से खतरा बढ जाने से शहरवासियों में हडकंप मचा नजर आ रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार 20 जून की सुबह 7 बजे के दौरान शहर के बाजपेयी वार्ड गौतमनगर निवासी राजकुमार नेताम हमेशा की तरह परिवार के सदस्यों के साथ मोक्षधाम परिसर में स्थित डम्पिंगयार्ड गया हुआ था। परिवार के लोग कचरे से कबाड चुन रहे थे। इसी दौरान झाडियों से निकले जंगली सूअर ने राजकुमार नेताम और चंदाबाई बेहरे पर पीछे से हमला कर घायल कर दिया। शोर मचाने के बाद सूअर मोक्षधाम परिसर की झाडियों से होकर जंगल की ओर भाग निकला। घायलों को उपचार के लिए जिला केटीएस अस्पताल में भर्ती किया गया है।

बताया जाता है कि गौतमनगर इलाके के सोनझारी समाज के लोग वर्षो से डम्पिंगयार्ड के कचरे से प्लास्टिक और लोहे की वस्तूएं चुनकर उदरनिर्वाह कर रहे है। इसके पूर्व भी मोक्षधाम परिसर में जंगली सूअरों के हमले की घटनाएं सामने आयी है। इलाके में खतरा बढ जाने से नागरिकों को सतर्क रहना जरुरी हो गया है। उसी तरह दूसरी घटना जिले के सडक अर्जुनी तहसील के ग्राम मालीजुंगा में घटीत हुई है। जिसमें मालीजुंगा निवासी सुभाष परतेकी और प्रमोद परतेकी दोनों दुपहिया से खेत से घर लौट रहे थे। इसी दौरान जंगली सूअरों के झूंड ने दोनों पर हमला कर दिया। घायलों पर ग्रामीण अस्पताल में प्राथमिक उपचार किया गया। पश्चात आगे के उपचार के लिए घायलों को जिला केटीएस अस्पताल में भेजा गया। घटना की जानकारी वनविभाग अधिकारियों को दे दी गई है। वनविभाग अधिकारियों द्वारा घटना का पंचनामा किए जाने का बताया गया है। परिजनों द्वारा आर्थिक मुआवजे की मांग की गई है।

## आमदार क्रिडा महोत्सव के उपरांत उत्कृष्ट कार्य के लिए

# वृक्षधरा फाउंडेशन नागराधाम का सत्कार

बुलंद गोंदिया - जनता के आमदार विनोद अग्रवाल के जन्मदिन के उपलक्ष पर 1 जून 2022 ते 5 जून तक आमदार क्रिडा महोत्सव का विभिन्न खेलों का आयोजन किया गया था। जिसमे विश्व पर्यावरण दिवस पर वृक्षधरा फाउंडेशन नागराधाम की टीम जिसने नागराधाम को हरियाली युक्त गांव बनाने का संकल्प लिया है, ऐसे टीम का पर्यावरण दिवस पर आमदार क्रिडा महोत्सव के उपरांत रोहित अग्रवाल और जनता की पार्टी चाबी संगठन के युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष समिर आरेकर, शहर अध्यक्ष अभय मानकर, शेखर शहारे ग्रामीण अध्यक्ष साथ मे युवा मोर्चा की पुरी द्वारा सत्कार किया गया। वृक्षधरा फाउंडेशन टीम के राकेश दमाहे, अजय दमाहे, अजय बारेवार, राजू भारती, रुपेश लिल्हारे, नितेश बारेवार, प्रकाश बूडेकर, सुरेद्र लिल्हारे, बबलू बारेवार, रमेश लिल्हारे, निलेश ढेकवार, सागर बनोटे, योगेश बारेवार, प्यूश भारती, वैभव दमाहे, शिवम बारेवार, महेश पगरवार और सुरेश लिल्हारे उपस्थित थे।

# केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना सेना के मूल्यों पर खरी नहीं

## गोंदिया जिला राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस की ओर से केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध

बुलंद गोंदिया - गोंदिया जिला राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस की ओर से केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध प्रदर्शन सरदार वल्लभभाई पटेल प्रतिमा के सामने पूर्व विधायक राजेंद्र जैन के नेतृत्व में युवक जिलाध्यक्ष केतन तुरकर एवम अन्य युवक साथियों के साथ धरना आंदोलन कर जिलाधिकारी गोंदिया को ज्ञापन सौंपा गया। गोंदिया जिले की सभी तहसीलों में राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस द्वारा तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। सैनिकों के वेतन एवं पेंशन कम करने के लिए अग्निपथ भर्ती योजना लागू की गई है। यह आर्मी की परंपरा, प्रकृति, नैतिकता और मूल्यों पर खरी नहीं है। सेना की क्षमता और प्रभाव पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। सेना को टूरिस्ट संगठन की तरह समझा जाने लगेगा।

### चार साल बाद क्या करेंगे नए फौजी

अग्निपथ योजना में भरती जवान को पौने तीन साल की ड्यूटी मिलेगी। उसके बाद छह माह ट्रेनिंग में निकल

जाएंगे। नौ महीने की छुट्टी भी होती है। इससे स्थायी नौकरी वाले फौजियों के ड्यूटी क्षेत्र पर भी असर पड़ेगा। चार साल बाद सेना से लौटने के बाद काम मिलना आसान नहीं होगा। उन्हें पूर्व सैनिकों का दर्जा भी नहीं मिलेगा।

योजना का सबसे ज्यादा विरोध पूर्व सैन्य अधिकारियों ने किया है। भर्ती नियमों के लिंक से हटकर लिया गया यह निर्णय सिर्फ धन बचाने के लिए है। इसमें सैन्य अभियानों की आवश्यकताओं और युद्ध के दौरान सैनिकों के कार्यकौशल की जरुरत को दरकिनार किया गया है। पूरी तरह से प्रशिक्षण न मिलने पर एक सैनिक किसी के भी जीवन को खतरे में डाल सकता है। अग्निपथ योजना के तहत प्रशिक्षण की जो अवधि तय की गई है वह एक कुशल सैनिक तैयार करने के लिए अपर्याप्त है। यह प्रशिक्षण महज कामचलाऊ होगा।

अग्निपथ योजना का विरोध प्रदर्शन करने पूर्व विधायक राजेन्द्र जैन, राजकुमार जैन, केतन तुरकर, अशोक सहारे, योगेद्र भगत, प्रेम रहांगडाले, विनीत सहारे, कुंदन कटारे, जिम्मी गुप्ता, नागों बंसोड़, अखिलेश सेठ, शैलेश वासनिक, सुनील पटले, कान्हा बघेले, एकनाथ वहिंले, लिवेश चिकलोंढे, कृष्णा भांडारकर, दर्पण वानखेड़े, अजय जमरे, राज शुक्ला, सतीश पारधी, कालू चौहान, प्रतीक भालेराव, कपिल बावनथड़े, कुणाल बावनथड़े, रौनक ठाकुर, नरेद्र बेलगे, पिंटु बनकर, आकाश नागपूरे, सौरभ मिश्रा, वामन गेडाम, करण टेकाम, मयुर दरबार, विजय रहांगडाले, ललित बिसेन, अनंत गोखे, यश जैस्वाल, पंकज चौधरी, राजेश नागपुरे, आरजु मेश्राम, श्रेयस खोब्रागडे, मयुर चौधरी, प्रतिक पारधी, अमन घोडीचोर, अनुराग बोरकर, देवदास बोरकर सहित अन्य उपस्थित थे।

# संपादकीय

## हिंसक विरोध

सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान देश की अर्थव्यवस्था को और पटरी से नीचे ले जाएगा। मगर सरकार से भी अपेक्षा की जाती है कि ऐसे मौकों पर वह बातचीत के जरिए हल निकालने का माहौल बनाए। चुप्पी साधे रखने से बात नहीं बनेगी। अगर सरकार के किसी फैसले को लेकर आंदोलन छिड़ता है, तो सरकार का फर्ज है कि उसे शांत करने की पहल करे, न कि दमन का रास्ता अख्तियार करे।

एक बार फिर नौजवान हिंसक आंदोलन पर उतर आए हैं। देश के विभिन्न शहरों में रेल की बोगियों, स्टेशनों, बसों आदि को आग के हवाले कर दिया गया। कहीं-कहीं भाजपा विधायकों के वाहनों, भाजपा कार्यालयों पर भी हमले हुए। यह सब सेना में भर्ती की नई नीति के विरोध में हो रहा है। सरकार ने अग्निपथ योजना के तहत सेना में चार साल के लिए भर्ती की नीति बनाई है, जिसमें न तो संतोषजनक वेतन तय किया गया है, न पेंशन और न दूसरी सुविधाओं को शामिल किया गया है।

कोरोना काल में दो साल सेना में भर्ती रुकी रही। फिर जब खोली गई है, तो नई योजना के तहत। सरकार ने इस योजना को विज्ञापनों के माध्यम से कुछ इस तरह बढ़-चढ़ कर प्रचारित किया, मानो इससे युवाओं को बहुत लाभ मिलने वाला है और भारतीय सेना अधिक ताकतवर होकर उभरेगी।

इस योजना की घोषणा रक्षामंत्री और सेना के तीनों प्रमुखों ने मिल कर की। मगर जैसे ही योजना का विवरण सार्वजनिक हुआ, नौजवानों का आक्रोश फूट पड़ा। सबने सवाल किया कि चार साल की ही चाकरी क्यों? उसके बाद नौजवान क्या करेंगे, कहां जाएंगे। हालांकि सरकार ने समझाने का प्रयास किया कि इस सेवा से निकलने के बाद युवाओं को दूसरे सुरक्षाबलों में जगह दी जाएगी, मगर इससे वे संतुष्ट नहीं हैं और आंदोलन बढ़ता जा रहा है।

हालांकि सरकार का कहना है कि उसने बहुत विचार-विमर्श और दूसरे देशों की रक्षा प्रणाली का अध्ययन करने के बाद इस योजना की रुपरेखा तैयार की है। इससे देश की सेना में सबसे ऊर्जावान युवाशक्ति होगी। कई देशों में ऐसी योजनाएं हैं कि वहां युवाओं को अपने जीवन के कुछ साल सेना को देने होते हैं, उसके बाद वे दूसरी सरकारी नौकरियों या अपने निजी काम-धंधों का चुनाव कर सकते हैं।

मगर हमारे देश में उस व्यवस्था की नकल नहीं की जा सकती, क्योंकि यहां दुनिया की सबसे अधिक बेरोजगार नौजवान आबादी है और उनमें से ज्यादातर सेना में इसलिए भी जाना चाहते हैं कि वहां जगहें अधिक निकलती हैं और उसमें पेंशन आदि की सुविधा लागू है। हमारे यहां भविष्य की सुरक्षा की चिंता अधिक है। दूसरे देशों में यह स्थिति नहीं है। मगर सरकार ने इस पक्ष पर या तो गंभीरता से विचार नहीं किया या उसे अपने खर्चे बचाने की चिंता अधिक थी। अब न केवल नौजवान, बल्कि अनेक रक्षा विशेषज्ञ और राजनीतिक दल इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं।

इस योजना को लागू करने के बाद अब भी सरकार ठीक से समझा पाने में विफल दिख रही है कि इसके लाभ क्या हैं। यही स्थिति कृषि कानूनों को लेकर थी। इस तरह इस आंदोलन के अभी और खिंचने के आसार हैं। किसी भी नीति या फैसले को लेकर एतराज होने पर विरोध प्रदर्शन करना नागरिकों का सांविधानिक अधिकार है। मगर अपनी बात मनवाने या सरकार पर दबाव बनाने के लिए हिंसा का सहारा किसी भी रुप में उचित नहीं कहा जा सकता। आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए।

सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान देश की अर्थव्यवस्था को और पटरी से नीचे ले जाएगा। मगर सरकार से भी अपेक्षा की जाती है कि ऐसे मौकों पर वह बातचीत के जरिए हल निकालने का माहौल बनाए। चुप्पी साधे रखने से बात नहीं बनेगी। अगर सरकार के किसी फैसले को लेकर आंदोलन छिड़ता है, तो सरकार का फर्ज है कि उसे शांत करने की पहल करे, न कि दमन का रास्ता अख्तियार करे।

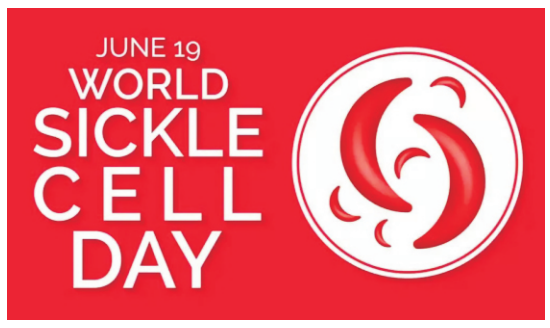


### सिकल-सेल रोग

सिकल-सेल रोग (SCD) या सिकल-सेल रक्ताल्पता या ड्रीपेनोसाइटोसिस एक आनुवंशिक रक्त विकार है जो ऐसी लाल रक्त कोशिकाओं के द्वारा चरितार्थ होता है जिनका आकार असामान्य, कठोर तथा हंसिया के समान होता है। यह क्रिया कोशिकाओं के लचीलेपन को घटाती है जिससे विभिन्न जटिलताओं का जोखिम उभरता है। यह हंसिया निर्माण, हीमोग्लोबिन जीन में उत्परिवर्तन की वजह से होता है। जीवन प्रत्याशा में कमी आ जाती है, एक सर्वेक्षण के अनुसार महिलाओं की औसत जीवन प्रत्याशा 48 और पुरुषों की 42 हो जाती है।

सिकल सेल रोग, आमतौर पर बाल्यावस्था में उत्पन्न होता है और प्राय: ऐसे लोगों (या उनके वंशजों में) में पाया जाता है जो उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय भागों में पाए जाते हैं तथा जहां मलेरिया सामान्यत: पाया जाता है। अफ्रीका के उप सहारा क्षेत्र के एक तिहाई स्वदेशियों में यह पाया जाता है, क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में जहां मलेरिया आम तौर पर पाया जाता है वहां जीवन का अस्तित्व तभी संभव है जब एक सिकल-कोशिका का जीन मौजूद हो. जिनके पास सिकल कोशिका रोग के दो युग्मविकल्पी में से एक ही हो वे मलेरिया के प्रति अधिक प्रतिरोधी होते हैं, क्योंकि मलेरिया प्लाज्मोडियम का पर्याक्रमण उन कोशिकाओं के हंसिया निर्माण से रुक जाता है जिस पर यह आक्रमण करता है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के अनुसार इस रोग की व्याप्ति संयुक्त राज्य अमेरिका में, 5000 में लगभग 1 है, जो मुख्यत: उप सहारा अफ्रीकी वंश के अमेरिकियों को प्रभावित करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में, 500 अश्वेत जन्म में से 1 को सिकल-सेल रक्ताल्पता होती है।

सिकल-सेल रक्ताल्पता, सिकल सेल रोग का एक विशिष्ट प्रकार है जिसमें उत्परिवर्तन के लिए सम्युग्मजता होती है जिसके कारण भी होता है। सिकल-सेल रक्ताल्पता को "HbSS" SS रोग, हीमोग्लोबिन S या उसके उत्परिवर्तन के रुप में जाना जाता है। विषमयुग्म वाले लोग, जिनके पास केवल एक सिकल जीन तथा एक सामान्य वयस्क हीमोग्लोबिन जीन हो, उन्हें "HbAS" या सिकल सेल लक्षण कहते हैं।

अन्य, दुर्लभ प्रकार के सिकल सेल रोगों में शामिल हैं, सिकल-हीमोग्लोबिन C (HbSC), सिकल बीटा-प्लस-थैलेसीमिया (HbS//β+) और सिकल बीटा-शून्य-थैलेसीमिया (HbS/β0). सिकल सेल के ये अन्य रुप यौगिक विषमयुग्मीय अवस्था हैं जिसमें व्यक्ति में उत्परिवर्तन की केवल एक प्रतिलिपि होती है जिसके कारण HbS होता है तथा एक अन्य असामान्य हीमोग्लोबिन युग्मविकल्पी की प्रतिलिपि होती है।

रोग शब्द इसलिए लागू होता है, क्योंकि विरासत में मिली असामान्यता एक रोग विज्ञान सम्बन्धी ऐसी जटिलता को उत्पन्न करती है जिससे मृत्यु अथवा अन्य जटिलता उत्पन्न हो सकती है। हीमोग्लोबिन के सभी अनुवांशिक प्रकार हानिकारक नहीं होते हैं, इस अवधारणा को आनुवंशिक बहुरुपता के रुप में जाना जाता है।

### रोग निदान

HbS में, पूर्ण रक्त गिनती हीमोग्लोबिन के स्तर को एक उच्च जाललोहितकोशिका गिनती के साथ 6-8 g/dL श्रेणी में दर्शाती है (चूंकि अस्थि मज्जा, अधिक लाल रक्त कोशिका को उत्पन्न करते हुए सिकल सेल के विनाश के लिए क्षतिपूर्ति करती है). सिकल सेल रोग के अन्य रुपों में, Hb स्तर अधिक हो जाता है। एक रक्त फिल्म) हाइपोस्प्लेनिज़म की सुविधाओं को दिखा सकती है। (लक्ष्य कोशिका और हॉवेल-जॉली निकाय)

लाल रक्त कोशिकाओं के हंसिया के रुप में निर्माण को, एक रक्त फिल्म पर, सोडियम मेटाबाईसल्फाईट के संयोजन द्वारा प्रेरित किया जा सकता है। सिकल हीमोग्लोबिन की उपस्थिति को षसिकल विलेयता परीक्षणष द्वारा भी प्रदर्शित किया जा सकता है। हीमोग्लोबिन S (Hb S) का मिश्रण, एक घटित घोल में जैसे (सोडिअम डाईथिओनाईट) एक गंदेला स्वरुप देता है, जबकि सामान्य Hb एक स्पष्ट घोल देता है।

असामान्य हीमोग्लोबिन रुपों को हीमोग्लोबिन वैद्युतकणसंचलन, जेल वैद्युतकणसंचलन का एक रुप जिस पर विभिन्न प्रकार के हीमोग्लोबिन गतिशील रहते हैं, पर खोजा जा सकता है। जेल वैद्युतकणसंचलन का एक रुप जिस पर विभिन्न प्रकार के हीमोग्लोबिन गतिशील रहते हैं, पर खोजा जा सकता है। सिकल सेल हीमोग्लोबिन (HgbS) और सिकल निर्माण के साथ हीमोग्लोबिन C (HgbSC) - दो सबसे आम रुप - को वहां से पहचाना जा सकता है। रोग निदान की उच्च प्रदर्शन तरल क्रोमैटोग्राफी (HPLC) द्वारा पुष्टि की जा सकती है। आनुवंशिक परीक्षण, को शायद ही कभी किया जाता है, चूंकि अन्य जांच HBC और HbS के लिए अत्यधिक विशिष्ट हैं।

एक तीव्र सिकल सेल संकट अक्सर संक्रमण द्वारा प्रबल हो जाता है। इसलिए, गुप्त मूत्र-पथ संक्रमण का पता लगाने के एक मूत्र जांच और गुप्त निमोनिया की जांच के लिए सीने के एक्स रे को नियमित तौर पर अपनाना चाहिए।

जो लोग इस रोग के ज्ञात वाहक हैं वे संतान होने से पहले अक्सर आनुवांशिक परामर्श से गुजरते हैं। यह जांचने के लिए कि एक अजन्मे बच्चे को यह रोग है कि नहीं, रक्त के एक नमूने को भ्रुण से लिया जाता है या अमिनिओटिक पदार्थ के नमूने को लिया जाता है। चूंकि एक भ्रुण से खून का नमूना लेने में अधिक जोखिम है, आमतौर पर बाद वाले परीक्षण का इस्तेमाल किया जाता है।

1979 में इस बीमारी के लिए जिम्मेदार उत्परिवर्तन को खोजे जाने के बाद, अमेरिकी वायु सेना में अश्वेत आवेदकों को उत्परिवर्तन की जांच कराना आवश्यक हो गया। इसने 143 आवेदकों को इसलिए खारिज कर दिया क्योंकि वे वाहक थे, हालांकि उनमें से कोई भी रोगी नहीं था। उसने अंतत: इस आवश्यकता को वापस ले लिया, लेकिन तभी जब एक प्रशिक्षु ने एक मुकदमा दायर किया।

## २३ जुन : अन्तरराष्ट्रीय ओलम्पिक दिवस

अन्तरराष्ट्रीय ओलम्पिक समिति (आईओसी) (अंग्रेज़ी : International Olympic Committee (IOC) फ्रान्सीसी : फ्रान्सीसी (CIO) एक अन्तर्राष्ट्रीय समिति है जिसका मुख्यालय स्विट्ज़रलैण्ड के लॉज़ेन में स्थित है। इसकी स्थापना पियरे डे कोबेर्टिन ने 23 जून 1894 को कि थी तथा यूनानी व्यापारी देमित्रिस विकेलस इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। वर्तमान समय में विश्व की कुल 205 राष्ट्रीय ओलम्पिक समितिया (एनओसी) इसकी सदस्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2022 का थीम एक साथ, एक शांतिपूर्ण दुनिया के लिए रखा गया है।

### इतिहास

आईओसी की स्थापना पियरे डे कोबेर्टिन द्वारा 23 जून 1894 को की गई थी। 23 जून को प्रति वर्ष ओलिंपिक दिवस के रुप में मनाया जाता है। जून 2017 तक, इसकी सदस्यता में 95 सक्रिय सदस्य, 41 मानद सदस्य, एक मानद अध्यक्ष (जैक्स रोगे) और एक सम्मान सदस्य (हेनरी किसिंजर) शामिल हैं। आईओसी दुनिया भर में आधुनिक ओलंपिक आंदोलन का सर्वोच्च शासी निकाय है। आईओसी हर चार साल मे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल, शीतकालीन ओलम्पिक खेल और युवा ओलम्पिक खेल का आयोजन करता है। आईओसी द्वारा आयोजित पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 1896 में यूनान के एथेंस व पहला शीतकालीन ओलंपिक 1924 में फ्रांस के चेमोनिक्स में आयोजित किया था। 1992 तक ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक दोनों एक ही वर्ष आयोजित किए जाते थे।

### कार्य और भूमिका

- अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्य कार्य ओलंपिक आंदोलन को बढ़ावा देना और ओलंपिक आंदोलन का नेतृत्व करना है।
- खेल और खेल प्रतियोगिताओं के संगठन, विकास और समन्वय को प्रोत्साहित करना और समर्थन करना।
- ओलंपिक खेलों के नियमित आयोजन को सुनिश्चित करना।
- सक्षम सार्वजनिक या निजी संगठनों और अधिकारियों के साथ सहयोग करने का प्रयास करना ताकि खेल द्वारा मानवता की सेवा और शांति को बढ़ावा मिले।
- ओलंपिक आंदोलन को प्रभावित करने वाले किसी भी प्रकार के भेदभाव के खिलाफ कार्य करना।
- पुरुषों और महिलाओं की समानता के सिद्धांत को लागू करने के दृष्टिकोण के साथ सभी स्तरों पर और सभी संरचनाओं में खेल में महिलाओं के प्रचार को प्रोत्साहित करना और समर्थन करना।

साभार : विकिपीडिया

# छत्रपति शाहू महाराज

शाहू, (जिन्हें राजर्षि शाहू महाराज, छत्रपति शाहू महाराज या शाहू महाराज भी कहा जाता है) मराठा के भोंसले राजवंश के (26 जून, 1874 - 6 मई, 1922) राजा (शासनकाल 1894-1900) और कोल्हापुर की भारतीय रियासतों के महाराजा (1900-1922) थे। उन्हें एक वास्तविक लोकतान्त्रिक और सामाजिक सुधारक माना जाता था। कोल्हापुर की रियासत राज्य के पहले महाराजा, वह महाराष्ट्र के इतिहास में एक अमूल्य मणि था। सामाजिक सुधारक ज्योतिराव गोविंदराव फुले के योगदान से काफी प्रभावित, शाहू महाराज एक आदर्श नेता और सक्षम शासक थे जो अपने शासन के दौरान कई प्रगतिशील और पथभ्रष्ट गतिविधियों से जुड़े थे। 1894 में अपने राजनेता से 1922 में उनकी मृत्यु तक, उन्होंने अपने राज्य में निचली जाति के विषयों के कारण अथक रुप से काम किया। जाति और पन्थ के बावजूद सभी को प्राथमिक शिक्षा उनकी सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में से एक थी।

### प्रारम्भिक जीवन

उनका जन्म कोल्हापुर जिले के कागल गाँव के घाटगे शाही मराठा परिवार में 26 जून, 1874 में जयश्रीराव और राधाबाई के रुप में यशवन्तराव घाटगे के रुप में हुआ था। जयसिंहराव घाटगे गाँव के प्रमुख थे, जबकि उनकी पत्नी राधाभाई मुधोल के शाही परिवार से सम्मानित थीं। नौजवान यशवन्तराव ने अपनी माँ को खो दिया जब वह केवल 3 वर्ष के थे। 10 साल की उम्र तक उनकी शिक्षा उनके पिता द्वारा पर्यवेक्षित की गई थी। उस वर्ष, उन्हें कोल्हापुर की रियासत राज्य के राजा शिवाजी चतुर्थ की विधवा रानी आनन्दबीई ने अपनाया था। यद्यपि उस समय के गोद लेने के नियमों ने निर्धारित किया कि बच्चे को अपने नस में भोसले राजवंश का खून होना चाहिए, यशवन्तराव की पारिवारिक पृष्ठभूमि ने एक अनोखा मामला प्रस्तुत किया। उन्होंने राजकुमार कॉलेज, राजकोट में अपनी औपचारिक शिक्षा पूरी की और भारतीय सिविल सेवा के प्रतिनिधि सर स्टुअर्ट फ्रेज़र से प्रशासनिक मामलों के सबक ले लिए। 1894 में उम्र के आने के बाद वह सिंहासन पर चढ़ गए, इससे पहले ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त एक राजसी परिषद ने राज्य मामलों का ख्याल रखा। अपने प्रवेश के दौरान यशवन्तराव का नाम छत्रपति शाहूजी महाराज रखा गया था। छत्रपति शाहू ऊँचाई में 5 फीट 9 इंच से अधिक था और एक शाही और राजसी उपस्थिति प्रदर्शित किया था। कुश्ती अपने पसन्दीदा खेलों में से एक थी और उन्होंने अपने पूरे शासन में इस खेल को संरक्षित किया था। पूरे देश के पहलवान कुश्ती प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए अपने राज्य आएँगे।

1891 में बड़ौदा के एक महान व्यक्ति की बेटी लक्ष्मीबाई खानविलाकर से उनका विवाह हुआ। इस जोड़े के चार बच्चे थे - दो बेटे और दो बेटियाँ।

### वेदोकता विवाद

जब शाही परिवार के ब्राम्हण पुजारी ने वैदिक भजनों के अनुसार गैर-ब्राम्हणों के संस्कार करने से इनकार कर दिया, तो उन्होंने पुजारियों को हटाने और गैर-ब्राम्हणों के धार्मिक शिक्षक के रुप में एक युवा मराठा को नियुक्ति के लिए साहसी कदम उठाया क्षत्र जगद्गुरु (क्षत्रिय के विश्व शिक्षक) के। इसे वेदोकता विवाद के रुप में जाना जाता था। यह उसके कानों के बारे में एक सींग का घोंसला लाया, लेकिन वह विपक्ष के चेहरे पर अपने कदमों को पीछे हटाने वाला आदमी नहीं था। वह जल्द ही गैर-ब्राम्हण आन्दोलन के नेता बने और मराठों को उनके बैनर के तहत एकजुट कर दिया। ख5,ख6,

### सामाजिक सुधार

छत्रपति शाहू ने 1894 से 1922 तक 28 वर्षों तक कोल्हापुर के सिंहासन पर कब्जा कर लिया, और इस अवधि के दौरान उन्होंने अपने साम्राज्य में कई सामाजिक सुधारों की शुरुआत की। शहू महाराज को निचली जातियों में से बहुत कुछ करने के लिए बहुत कुछ करने का श्रेय दिया जाता है और वास्तव में यह मूल्यांकन जरुरी है। उन्होंने इस प्रकार शिक्षित छात्रों के लिए उपयुक्त रोजगार सुनिश्चित किया, जिससे इतिहास में सबसे पुरानी सकारात्मक कार्रवाई (कमजोर वर्गों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण) कार्यक्रमों में से एक बना। इन उपायों में से कई को 26 जुलाई को 1902 में प्रभावित किया गया था। उन्होंने रोजगार प्रदान करने के लिए 1906 में शाहू छत्रपति बुनाई और स्पिनिंग मिल शुरु की। राजाराम कॉलेज शाहू महाराज द्वारा बनाया गया था और बाद में इसका नाम उनके नाम पर रखा गया था। उनका जोर शिक्षा पर था और उनका उद्देश्य लोगों को शिक्षा उपलब्ध कराने का था। उन्होंने अपने विषयों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई शैक्षणिक कार्यक्रम शुरु किए। उन्होंने विभिन्न जातियों और धर्मों जैसे पंचल, देवदान्य, नाभिक, शिंपी, धोर-चंभहर समुदायों के साथ-साथ मुसलमानों, जैनों और ईसाइयों के लिए अलग-अलग छात्रावास स्थापित किए। उन्होंने समुदाय के सामाजिक रुप से संगठित खंडों के

लिए मिस क्लार्क बोर्डिंग स्कूल की स्थापना की। उन्होंने पिछड़ी जातियों के गरीब लेकिन मेधावी छात्रों के लिए कई छात्रवृत्तियां पेश कीं। उन्होंने अपने राज्य में सभी के लिए एक अनिवार्य मुफ्त प्राथमिक शिक्षा भी शुरु की। उन्होंने वैदिक स्कूलों की स्थापना की जिन्होंने सभी जातियों और वर्गों के छात्रों को शास्त्रों को सीखने और संस्कृत शिक्षा को प्रचारित करने में सक्षम बनाया। उन्होंने बेहतर प्रशासकों में उन्हें बनाने के लिए गांव के प्रमुखों या पैटिल के लिए विशेष विद्यालय भी शुरु किए।

छत्रपति साहू समाज के सभी स्तरों के बीच समानता का एक मजबूत समर्थक था और ब्राम्हणों को कोई विशेष दर्जा देने से इनकार कर दिया। उन्होंने ब्राम्हणों को रॉयल धार्मिक सलाहकारों के पद से हटा दिया जब उन्होंने गैर ब्राम्हणों के लिए धार्मिक संस्कार करने से इंकार कर दिया। उन्होंने पद में एक युवा मराठा विद्वान नियुक्त किया और उन्हें क्षत्र जगद्गुरु (क्षत्रिय के विश्व शिक्षक) का खिताब दिया। यह घटना शाहु के गैर-ब्राम्हणों को वेदों को पढ़ने और पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ महाराष्ट्र में वेदोकता विवाद का कारण बन गई। वेदोकता विवाद ने समाज के अभिजात वर्ग के विरोध से विरोध का तूफान लायाय छत्रपति के शासन का एक दुष्परिणाम। उन्होंने 1916 के दौरान निपानी में दक्कन रायट एसोसिएशन की स्थापना की। एसोसिएशन ने गैर ब्राम्हणों के लिए राजनीतिक अधिकारों को सुरक्षित करने और राजनीति में उनकी समान भागीदारी को आमंत्रित करने की मांग की। शाहुजी ज्योतिबा फुले के कार्यों से प्रभावित थे, और उन्होंने फुले द्वारा गठित सत्य शोधक समाज का संरक्षण किया। अपने बाद के जीवन में, हालांकि, वह आर्य समाज की तरफ चले गए।

1903 में, उन्होंने किंग एडवर्ड टप्ए और रानी अलेक्जेंड्रा के कोरोनेशन में भाग लिया, और उस वर्ष मई में उन्हें मानद उपाधि एलएलडी प्राप्त हुई। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से।

छत्रपति शाहू ने जाति अलगाव और अस्पृश्यता की अवधारणा को खत्म करने के लिए बड़े प्रयास किए। उन्होंने अस्पृश्य जातियों के लिए सरकारी नौकरियों में (शायद पहली ज्ञात) आरक्षण प्रणाली शुरु की। उनके रॉयल डिक्री ने अपने विषयों को समाज के हर सदस्य के बराबर और अछूतों को कुएं और तालाबों के साथ-साथ स्कूलों और अस्पतालों जैसे प्रतिष्ठानों के समान उपयोग के लिए समानता प्रदान करने का आदेश दिया। उन्होंने अंतर जाति विवाह को वैध बनाया और दलितों के उत्थान के लिए बहुत सारे प्रयास किए। उन्होंने राजस्व कलेक्टरों (कुलकर्णी) के खिताब और कार्यकाल के वंशानुगत हस्तान्तरण को बन्द कर दिया, जो जनता का शोषण करने के लिए कुख्यात जाति, विशेष रुप से महारों का दास, निचली जाति।

छत्रपति ने अपने साम्राज्य में महिलाओं की स्थितियों के सुधार की दिशा में भी काम किया। उन्होंने महिलाओं को शिक्षित करने के लिए स्कूलों की स्थापना की, और महिलाओं की शिक्षा के विषय पर जोरदार बात की। उन्होंने देवदासी प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून की शुरुआत की, जो लड़कियों को भगवान की पेशकश करने का अभ्यास था, जिसने अनिवार्य रुप से पादरी के हाथों लड़कियों का शोषण किया। उन्होंने 1917 में विधवा पुनर्विवाहों को वैध बनाया और बाल विवाह को रोकने के प्रयास किए।

उन्होंने कई परियोजनाएँ शुरु की जो अपने विषयों को अपने चुने हुए व्यवसायों में आत्मनिर्भर बनाने में सक्षम बनाती हैं। शाहु छत्रपति स्पिनिंग और बुनाई मिल, समर्पित बाजार स्थान, किसानों के लिए सहकारी समितियों की स्थापना छत्रपति ने अपने विषयों को व्यापार में मध्य पुरुषों से कम करने के लिए पेश की थी। उन्होंने कृषि प्रथाओं का आधुनिकीकरण करने के लिए उपकरण खरीदने के लिए किसानों को क्रेडिट उपलब्ध कराया और किसानों को फसल उपज और संबंधित प्रौद्योगिकियों को बढ़ाने के लिए किसानों को सिखाने के लिए राजा एडवर्ड कृषि संस्थान की स्थापना की। उन्होंने 18 फरवरी, 1907 को राधागारी बांध की शुरुआत की और परियोजना 1935 में पूरी हो गई। बाँध छत्रपति शाहू के दृष्टिकोण को उनके विषयों के कल्याण के प्रति प्रमाणित करता है और कोल्हापुर को पानी में आत्मनिर्भर बना देता है।

वह कला और संस्कृति का एक महान संरक्षक था और संगीत और ललित कला से कलाकारों को प्रोत्साहित करता था। उन्होंने लेखकों और शोधकर्ताओं को उनके प्रयासों में समर्थन दिया। उन्होंने जिमनासियम और कुश्ती पिच स्थापित किए और युवाओं के बीच स्वास्थ्य चेतना के महत्व पर प्रकाश डाला।

सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक, कृषि और सांस्कृतिक क्षेत्रों में उनके मौलिक योगदान ने उन्हें राजर्षि का खिताब अर्जित किया, जिसे कानपुर के कुर्मी योद्धा समुदाय ने उन्हें दिया था।

### डॉ अम्बेडकर के साथ एसोसिएशन

छत्रपति को भीमराव आम्बेडकर को कलाकार दत्ताबा पवार और दलवी ने पेश किया था। युवा भीमराव की महान बुद्धि और अस्पृश्यता के बारे में उनके क्रान्तिकारी विचारों से राजा बहुत प्रभावित हुए। दोनों ने 1917-1921 के दौरान कई बार मुलाकात की और जाति अलगाव के नकारात्मकों को खत्म करने के सम्भावित तरीकों से आगे बढ़े। 21-22, 1920 के दौरान अस्पृश्यों के सुधार के लिए उन्होंने एक सम्मेलन का आयोजन किया और छत्रपति ने डॉ आम्बेडकर को अध्यक्ष बना दिया क्योंकि उनका मानना था कि डॉ अम्बेडकर नेता थे जो समाज के अलग-अलग हिस्सों में सुधार के लिए काम करेंगे। उन्होंने रुपये दान भी किया। डॉ आम्बेडकर को 2,500 जब उन्होंने 31 जनवरी, 1921 को अपना अखबार मूकनायक शुरु किया, और उसी कारण के लिए बाद में योगदान दिया। उनका संगठन 1922 में छत्रपति की मृत्यु तक चली।

### व्यक्तिगत जीवन

1891 में, शाहू ने बड़ौदा के मराठा महान व्यक्ति की बेटी लक्ष्मीबाई खानविलाकर (1880-1945) से शादी की। वे चार बच्चों के माता-पिता थे।

राधाबाई अक्कासाहेब पुअर, देवास (सीनियर) (1894-1973) की महारानी, जिन्होंने देवास (सीनियर) के राजा तुकोजीराव तृतीय से शादी की थी और उन्हें मुद्दा था : विक्रमसिंहराव पुआर, जो 1937 में देवास (सीनियर) के महाराजा बने और बाद में शाहजी द्वितीय के रुप में कोल्हापुर के सिंहासन में सफल हुए। श्रीमान महाराजक कुमार शिवाजी (1899-1918) । श्रीमती राजकुमारी औबाई (1895) युवा की मृत्यु हो गई।

### मृत्यु

महान सामाजिक सुधारक छत्रपति शाहूजी महाराज की मृत्यु 6 मई, 1922 को हुई थी। वह अपने सबसे बड़े पुत्र राजाराम तृतीय को कोल्हापुर के महाराजा के रुप में सफल हुए थे। यह दुर्भाग्यपूर्ण था कि छत्रपति शाहू द्वारा शुरु किए गए सुधारों ने धीरे-धीरे विरासत को आगे बढ़ाने के लिए सक्षम नेतृत्व की कमी के लिए संघर्ष करना शुरु कर दिया।

साभार : विकिपीडिया

# विश्व सिकल सेल रोग नियंत्रण दिवस विशेष

बुलंद गोंदिया - सिकल सेल रोग के बारे में लोगों में जागरुकता पैदा करने के लिए, राज्य में हर साल 19 जून को सिकल सेल नियंत्रण दिवस मनाने का निर्देश दिया है। जिसमे जिले के सभी प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र, ग्रामीण रुग्णालय, उपजिला रुग्णालयात में नि:शुल्क सिकलसेल संबधित सोल्युबिलिटी जांच करने की जानकारी जिला आरोग्य अधिकारी डॉ. नितीन वानखेडे ने दी ।

जिले में एक से 30 वर्ष आयु वर्ग के सभी व्यक्तियों के लिए नि:शुल्क सिकल सेल स्क्रीनिंग एवं सिकल सेल रोग नियंत्रण कार्यक्रम पर मार्गदर्शन, सभी मरीजों को नि:शुल्क दवा व परामर्श दिया जा रहा है। सिकल सेल एक अनुवांशिक बीमारी है। इस बीमारी का कोई पूर्ण इलाज नहीं है लेकिन नियंत्रण संभव है। विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए क्योंकि सिकल सेल रोगियों को नियमित संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। हालांकि अपर जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. दिनेश सुतार ने जिले के युवाओं से अपील की है कि वे आगे आएं और सिकल सेल पर घुलनशीलता जांच कराएं। अमरीश मोहबे ने कहा सिकल सेल रोग वंशानुगत है लेकिन संक्रामक नहीं है।

गोंदिया जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सिकल सेल रोग नियंत्रण कार्यक्रम सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया जा रहा है। गोंदिया जिले में इस समय 12328 कैरियर और 1268 मरीजों का इलाज चल रहा है ऐसी जानकारी सपना खंडैत ने दी है। साथ ही जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में प्रयोगशाला वैज्ञानिक अधिकारियों द्वारा सिकल सेल घुलनशीलता परीक्षण किया जा रहा है और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ग्रामस्तर के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और आशासेवकां द्वारा रक्त परीक्षण और परामर्श नि:शुल्क किया जा रहा है। सिकल सेल घुलनशीलता परीक्षण के बाद सकारात्मक रोगियों के रक्त के नमूने वैद्युतकणसंचलन परीक्षण या एचपी हैं। एल.सी. जिले में कुल पांच केंद्रों पर परीक्षण किया जा रहा है, क्योंकि परीक्षण के माध्यम से उचित निदान की आवश्यकता होती है। परीक्षण जिला सामान्य अस्पताल गोंदिया, महिला अस्पताल, ग्रामीण अस्पताल राजेगांव, ग्रामीण अस्पताल आमगांव, ग्रामीण अस्पताल देवरी में आयोजित किए जाते हैं। यह इस कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित प्रशिक्षित प्रयोगशाला तकनीशियनों के माध्यम से किया जा रहा है।

जिले में सिकल सेल रोगियों के लिए आवश्यक दवाओं का स्टॉक प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर उपलब्ध है। सरकार ने जिला सामान्य अस्पताल में एक दिवसीय देखभाल केंद्र और एक महिला अस्पताल की स्थापना की है ताकि सिकल सेल रोगियों के लिए ग्रामस्तर के रोगियों को उचित और समय पर मुफ्त इलाज और दवा उपलब्ध हो सके। इस दिन के लिए दो सिकल सेल सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। सिकल सेल रोगियों के लिए सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं लागू की जाती हैं -

1) दसवीं और बारहवीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों के पास परीक्षा के दौरान प्रति घंटे बीस मिनट अधिक अवधि दी गई है।
2) सिकल सेल रोगियों को संजय गांधी निराधार योजना के तहत प्रति माह 1000 रुपये दिए जाते हैं।
3) विभिन्न योजनाओं का लाभ सिकल सेल रोगियों के रुप में विकलांगता सूची में शामिल है।
4) सिकल सेल रोगियों को आगे के इलाज के लिए बस यात्रा में रियायत दी जाती है।
5) सिकल सेल पीड़ितों के लिए नि:शुल्क रक्ताधान सुविधा।
6) सिकल सेल रोगियों के लिए नि:शक्तता प्रमाणपत्र सुविधा जिला सामान्य अस्पताल एवं शासकीय महाविद्यालय यहां उपलब्ध है।

सीखना -

सिकल सेल सामान्य लाल रक्त कोशिकाएं गोल और लचीली होती हैं, जबकि सिकल सेल लाल रक्त कोशिकाएं धुरी के आकार की और कड़ी होती हैं।

लक्षण -

कमजोरी, जोड़ों का दर्द, जोड़ों में सूजन, शरीर का पीला पड़ना, असहनीय दर्द, छोटे बच्चों में बार-बार संक्रमण होना।

जांच-

एक उंगली से रक्त की एक बूंद लेकर घुलनशीलता परीक्षण किया जाता है।

यदि परीक्षण सकारात्मक है, तो हीमोग्लोबिन वैद्युतकणसंचलन परीक्षण किया जाता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर सिकल सेल घुलनशीलता परीक्षण नि:शुल्क है।

शादी करने का फैसला करने से पहले लड़के और लड़की दोनों के खून की जांच करें। इस तरह की शादी से बचें-

1) यदि दोनों वाहक हैं
2) यदि एक वाहक और एक पीड़ित है
3) यदि दोनों पीड़ित हैं

क्योंकि उनकी संतानों को यह रोग हो सकता है

उपलब्ध सेवाएं -

1) सिकल सेल के सभी रोगियों को फोलिक एसिड की नि:शुल्क गोलियां प्रदान की जाती हैं।
2) मरीजों को दर्द निवारक दवाएं दी जाती हैं।
3) संक्रमण का इलाज एंटीबायोटिक दवाओं से किया जा सकता है।
4) जटिल रोगियों को मेडिकल कॉलेज में ले जाना।
5) जिन रोगियों को आधान की आवश्यकता है, उन्हें जिला अस्पताल में रक्त आधान की सुविधा प्रदान करना।

# स्कूल ऑफ डॉ. आंबेडकर थॉट्स

बुलंद गोंदिया - विश्वभूषण, भारतरत्न, परमपूज्य डॉ. बाबासाहब आंबेडकर सार्वजनिक जयंती उत्सव समिती, गोंदिया (वर्ष 42वा) द्वारा स्कूल ऑफ डॉ. आंबेडकर थॉट्स का आयोजन किया गया। समाज में बाबासाहब के मूल विचारो को प्रसारित करने एवं आंबेड़करी जनता में जनजागृति लाने के उद्देश्य से समिती ने हर माह के तीसरे रविवार को स्कूल आयोजन का निर्णय लिया है। स्कूल का विधिवत उद्घाटन प्रमुख वक्ता एवम शिक्षक आंबेडकरी विचारवंत आदरणीय रमेश जीवने द्वारा किया गया। स्कूल के प्रथम सत्र में रमेश जीवने द्वारा साउथबोरो कमीशन से लेकर धम्म क्रांति तक के कालखंड की जानकारी संक्षेप में दी गई। स्कूल के द्वितीय सत्र में सहभागियों द्वारा पूछे गए विविध प्रश्नों का निराकरण जीवने सर द्वारा किया गया। तथा तृतीय सत्र में सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक, आर्थिक एवं राजनैतिक विषयों पर खुली चर्चा की गई।

## कामगार कल्याण केंद्र तिरोड़ा में
# विश्व योग दिवस

बुलंद गोंदिया - महाराष्ट्र कामगार कल्याण केंद्र तिरोड़ा द्वारा विश्व योग दिवस के अवसर पर 21 जून को सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल तिरोड़ा में महाराष्ट्र भवन निर्माण कामगारों एवं वेतन भुगतान श्रमिक कल्याण कोष के लिए योग प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को मानव जीवन शैली में योग के महत्व के बारे में बताया गया और योग प्रशिक्षण दिया गया। मुख्य अतिथि के रुप में प्रधानाचार्य विशाल वेरुलकर और योग प्रशिक्षक गौरी जोशी उपस्थित थे। केंद्र के निदेशक ताम्रदीप जांभूलकर ने कार्यक्रम का संचालन व उपस्थित नागरिको का धन्यवाद किया। कार्यक्रम की सफलता के लिए कल्पना बोहने और सुनंदा सेलोकर ने किया सहयोग।

## कृषि संजीवनी सप्ताह का आयोजन
# २५ जून से १ जुलाई तक

बुलंद गोंदिया - स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत 25 जून से 1 जुलाई 2022 तक जिले में कृषि संजीवनी सप्ताह अभियान का आयोजन किया जायेगा। 25 जून को विभिन्न फसलों का प्रौद्योगिकी संवर्धन, मूल्य श्रृंखला सुदृढ़ीकरण दिवस, 26 जून को पौष्टिक अनाज दिवस, 27 जून को महिला कृषि प्रौद्योगिकी सशक्तिकरण दिवस, 28 जून को उर्वरक बचत दिवस, 29 जून को प्रगतिशील किसान संवाद दिवस, जून को कृषि व्यवसाय प्रौद्योगिकी दिवस 30. हैं।

स्वर्गीय वसंतराव नाइक के जन्मदिन 1 जुलाई को पूरे महाराष्ट्र में कृषि दिवस के रुप में मनाया जाता है। चूंकि यह अवधि खरीफ फसलों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इस दौरान कृषि विभाग के अधिकारी और कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक किसानों के बांधों का दौरा कर नई तकनीकों का प्रचार-प्रसार करेंगे। कृषि प्रौद्योगिकी में छोटे सुधार भी फसल उत्पादन वृद्धि पर बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। जिला कृषि अधीक्षक ने जिले के अधिक से अधिक किसानों से इस कृषि पुनरोद्धार सप्ताह के साथ-साथ विभिन्न अभियानों में भाग लेने की अपील की है।

# मानवता और योग

भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा और उसे मान लिया गया।

योग भारत की प्राचीन विद्या है। इसे अध्यात्म तक पहुंचने का प्राथमिक सोपान माना जाता रहा है। इसलिए पिछली सदी तक योग की पहुंच आम जन तक नहीं थी। इसकी साधना अध्यात्म से जुड़े लोग ही किया करते थे। हालांकि भारत से योग विद्या सीख कर अन्य देशों के लोगों ने भी अपने यहां इसका विकास किया। कई भारतीय योग गुरुओं ने विदेशों में जाकर इस विद्या का प्रचार-प्रसार किया। पर भारत में जन-जन तक योग की पहुंच कुछ सालों पहले ही बन पाई। इसमें भारत सरकार की पहल भी काफी महत्त्वपूर्ण रही।

भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा और उसे मान लिया गया। उसके बाद से योग की प्रतिष्ठा बहुत तेजी से बढ़ी है। इस बार आठवां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। हर साल योग शिविरों की संख्या बढ़ रही है। यह लोगों में योग के प्रति बढ़ते विश्वास का ही नतीजा है। कई राज्य सरकारें भी अपने यहां मुयत योग शिक्षक उपलब्ध कराने लगी हैं, जो मुहल्लों के पार्कों आदि में योग का प्रशिक्षण देते और योग कराते हैं। जबसे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाने लगा है, न केवल भारत, बल्कि दुनिया भर में योग शिविरों का आयोजन लगातार बढ़ता जा रहा है।

दरअसल, अब यह स्थापित हो चुका है कि योग केवल अध्यात्म का माध्यम नहीं, स्वस्थ रहने के लिए भी एक जरुरी माध्यम है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी स्वीकार कर लिया है कि योग से अनेक रोगों का इलाज किया जा सकता है। बहुत सारे अस्पतालों में अब योग पद्धति से चिकित्सा के विभाग खोले गए हैं। अब तो बहुत सारे डाक्टर भी दवा के साथ-साथ योगाभ्यास का सुझाव लिखते हैं। हालांकि इसका अलग से अध्ययन नहीं है कि योग के माध्यम से कितने लोगों के रोग दूर हुए, पर आम अनुभव इसके गवाह हैं कि नियमित योग से बड़े पैमाने पर लोगों की हृदय, यकृत, हड्डी, पाचन, रक्त शर्करा आदि संबंधी समस्याएं काफी हद तक ठीक हुई हैं।

इस तरह योग हमारे ही नहीं, कई देशों के सार्वजनिक चिकित्सा संबंधी खर्चों में कमी लाने में सहायक सिद्ध हो रहा है। इसके अलावा चूंकि सरकारें सार्वजनिक योग शिक्षक नियुक्त करने लगी हैं, स्कूलों आदि में भी योग शिक्षकों की भर्ती होने लगी है। जगह-जगह योग चिकित्सा के केंद्र खुल रहे हैं, लोगों का योग केंद्रों पर सलाह लेने के लिए उसी तरह भीड़ जुटने लगी है, जैसे अस्पतालों में उमड़ती है, इसलिए यह विद्या अब बड़े पैमाने पर रोजगार का अवसर भी उपलब्ध करा रही है।

आधुनिक समय में लोगों के जीवन में अनेक जटिलताएं पैदा हुई हैं। हर साल स्वास्थ्य संबंधी अध्ययनों में दर्ज होता है कि दुनिया में लाखों लोग मानसिक रोगों के शिकार हो रहे हैं। जीवन शैली संबंधी बीमारियां बहुत तेजी से लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रही हैं। इन बीमारियों के इलाज में अंग्रेजी पद्धति की चिकित्सा कारगर साबित नहीं हो रही। तमाम चिकित्सा विज्ञानी योग की मदद लेने का सुझाव देते देखे जा रहे हैं। ऐसे में अगर भारत ने पूरी दुनिया में लोगों को योग के प्रति जागरुक करने का संकल्प लिया है और उसमें कामयाब हो रहा है, तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। योग को और कारगर बनाने, इसकी पहुंच सुगम बनाने के लिए और क्या उपाय हो सकते हैं, इस पर विचार होना चाहिए। मानवता के विकास के लिए योग का प्रसार अनिवार्य रुप से होना चाहिए।

# टीटीई ने मानसिक पीड़िता गर्भवती की मददकर कायम की मानवता की मिसाल

बुलंद गोंदिया - दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर में कार्यरत कर्मचारी टीटीई ने मानसिक स्वास्थ्य पीड़ित महिला की मदद कर मानवतावादी का परिचय दिया है। वरिष्ठ टीकट परिक्षक आशुतोषकुमार सिंह की ड्यूटी ट्रेन ने 20814 में लगी थी। नागपुर से ट्रेन छूटने के बाद टीटीई आशुतोष अपने डिब्बे चेक करने गए कोच एस 6 में चेकिंग के दौरान उन्हें एक महिला मिली, जिसकी मानसिक हालत खराब थी। महिला का नाम आधार कार्ड में मिनाती मिर्धा पति रामचद्र मिर्धा बालेश्वर ओड़िशा है। महिला प्रेगनेंसी

की अंतिम तिथि के करीब थी एवं दर्द से बहुत ही जोर जोर से रो रही थी। टीटीई द्वारा तुरंत ही नागपुर वाणिज्य नियंत्रक को सूचना दी गई। तत्पश्चात गोंदिया रेसुब को सूचित किया गया। रेसुब एवं सहयोगी टीटीओ की सहायता से उस महिला को गोंदिया में गंगाबाई हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। उपस्थित डॉक्टर ने बताया की महिला की स्थिति खराब है एवं नवजात बच्चे का सिर बाहर निकल गया है। डॉक्टरों के प्रयासों से महिला की डिलीवरी हो पाई है। जच्चा-बच्चा दोनों स्वस्थ बताए जा रहे हैं। महिला के परिवार से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है।

# स्टेशन परिसर में बांस से बने उत्पादों की बिक्री

बुलंद गोंदिया - रेलवे की एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के तहत गोंदिया स्टेशन पर बांस से बनी वस्तुओं की बिक्री की जा रही है। केंद्र के पायलट प्रोजेक्ट के रुप में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, नागपुर मंडल के अंतर्गत गोंदिया स्टेशन प्लेटफार्म क्रमांक 1 पर नंदकिशोर साखरे (सालेकासा) द्वारा इस योजना के तहत बांस से बनी वस्तुओं की बिक्री 15 दिनों के लिए शुरु की गई है। इस योजना के तहत फॉरेस्ट प्रोडक्ट, होम मेड प्रोडक्ट एवं स्थानीय कला से निर्मित वस्तुओं की बिक्री स्टेशनों में की जा रही है। जिससे स्थानीय कला को बढ़ावा मिल रहा है। रेलवे की व्यापक पहुंच और महत्व को देखते हुए स्थानीय उत्पादों को देश भर में लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट में वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना की घोषणा की गई थी। इच्छुक व्यापारियों एवं संस्थाओं से स्टॉल लेने की विनंती की गई है।

स्टॉल लेने हेतु व्यापारी एवं संस्थाएं गोंदिया स्टेशन प्रबंधक एवं संबंधित वाणिज्य अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। मंडल रेल प्रबंधक मनिंदरसिंह उप्पल एवं वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक रवीशकुमार सिंह का कहना है कि इस योजना से महाराष्ट्र के स्थानीय उत्पादकों को वैश्विक पहचान दिलाने में मदद मिलेगी। इस अवसर पर स्टेशन प्रबंधक एच.एल. कुशवाहा, मुख्य वाणिज्य निरीक्षक प्रमोद बी. कन्हाडे, वाणिज्य निरीक्षक नितिन पाटिल, सुजीत कुमार, रेल सलाहकार समिति सदस्य इंजि.जसपाल सिंह चावला व आदि उपस्थित थे।

# लंबा हुआ जीवन

आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलता है कि इस राष्ट्रीय औसत के पीछे कई जटिलताएं छिपी हैं, जो बताती हैं कि देश के अलग-अलग हिस्सों और देशवासियों के अलग-अलग समूहों की विशिष्ट सचाइयां हैं, जिन पर अलग से ध्यान देने की जरुरत है। अगर सबसे पहले देखा जाए तो आखिर जीवन प्रत्याशा के मोर्चे पर आगे बढ़ने में सबसे बड़ी बाधा क्या है तो कुछ संकेत तो इन्हीं आंकड़ों से मिल जाते हैं।

बढ़ गई भारतीयों की उम्र

यह देखना राहत की बात है कि 2015 से 2019 की अवधि में देश में जीवन प्रत्याशा (लाइफ एक्सपेक्टेंसी) बढ़कर 69.7 वर्ष हो गई है। हालांकि अभी भी यह वैश्विक औसत (72.6 वर्ष) से कम है। बहरहाल, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के इन आंकड़ों पर गौर करने से इस राष्ट्रीय औसत के पीछे छिपी कई जटिलताएं सामने आती हैं, जो बताती हैं कि देश के अलग-अलग हिस्सों और देशवासियों के अलग-अलग समूहों की विशिष्ट सचाइयां हैं, जिन पर अलग से ध्यान देने की जरुरत है। लेकिन सबसे पहले अगर यह देखें कि आखिर जीवन प्रत्याशा के मोर्चे पर आगे बढ़ने में सबसे बड़ी बाधा क्या है तो कुछ संकेत तो इन्हीं आंकड़ों से मिल जाते हैं। जीवन प्रत्याशा में यह देखा जाता है कि अगर स्वास्थ्य से संबंधित सारी स्थितियां जस की तस रहीं तो भविष्य में व्यक्ति के कितने साल जीने की उम्मीद की जा सकती है। एसआरएस के ये आंकड़े बताते हैं कि जन्म के समय आंकी गई जीवन प्रत्याशा और एक वर्ष या पांच वर्ष की उम्र में आंकी गई जीवन प्रत्याशा में सबसे ज्यादा अंतर उन्हीं राज्यों में देखा गया, जहां शिशु मृत्यु दर सबसे ज्यादा है।

जाहिर है, इन राज्यों में गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य, प्रसूति के हालात और शिशुओं के कुपोषण के मोर्चे पर काम करके ही जीवन प्रत्याशा में वैश्विक स्तर तक पहुंचा जा सकता है। मगर अपने देश की बात करें तो पिछले चार पांच दशकों की अवधि में जीवन प्रत्याशा में संतोषजनक बढ़ोतरी दिखती है। 1970-75 की अवधि में जीवन प्रत्याशा महज 49.7 साल थी, जो अब यानी 2015-20 में 69.7 साल दर्ज की गई है। 45 साल की अवधि में जीवन प्रत्याशा में 20 साल की बढ़ोतरी कोई मामूली बात नहीं है। चूंकि जीवन प्रत्याशा मानव विकास को मापने का एक अहम और प्रचलित पैमाना है, इसलिए इसमें सुधार का मतलब कई मोर्चों पर सुधार होता है। उदाहरण के लिए, शिशु मृत्यु दर को लें तो 1970 में यह 132 प्रति 1000 शिशु थी, जो 2020 में 32 प्रति हजार शिशु रह गई थी। ऐसे ही प्रसूति के दौरान महिलाओं की मृत्य के आंकड़े 1990 में प्रति दस हजार महिलाओं पर 556 थे, जो 2018 में 113 प्रति दस हजार पर आ गए थे। बावजूद इसके, हमें याद रखना होगा कि यह पूरे देश की स्थिति नहीं है। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में जीवन प्रत्याशा अभी भी क्रमशरु 65.6 और 65.3 वर्ष ही है। शहरी और ग्रामीण इलाकों में जीवन प्रत्याशा का अंतर तो महत्वपूर्ण है ही, यह भी गौर करने लायक है कि केरल में ग्रामीण जीवन प्रत्याशा शहरों के मुकाबले ज्यादा है और यह भी कि बिहार, झारखंड में महिला जीवन प्रत्याशा पुरुषों के मुकाबले कम है। आगे बढ़ने का कोई भी रोडमैप इन विपरीतताओं को ध्यान में रखते हुए ही तैयार किया जा सकता है।

दिल्ली की जीवन प्रत्याशा 75.9 साल है जो देश में सबसे ज्यादा है। इसके बाद केरल, जम्मू और कश्मीर का नंबर आता है। छत्तीसगढ़ की जीवन प्रत्याशा देश में सबसे कम है। सबसे कम जीवन प्रत्याशा वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश का नंबर दूसरा है। यूपी की जीवन प्रत्याशा 65.3 साल है। हालांकि 1970-75 में यूपी की जीवन प्रत्याशा सिर्फ 43 साल थी। यानी इसमें 22.6 साल का इजाफा हुआ है।

# त्रुटिपूर्ण सर्वे का खामियाजा किसान क्यों भुगतें?

## धान खरीदी की मर्यादा बढ़ाएं सरकार - चाबी संगठन

बुलंद गोंदिया - वर्ष 2021-22 के रब्बी फसल (धान) की खरीदी शासकीय समर्थन मूल्य के आधार पर करने जो लक्ष्य मर्यादा (15 लाख क्विंटल) केंद्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र में निश्चित की गई, वो कृषि अधिकारियों द्वारा भेजी गई त्रुटिपूर्ण सर्वे की गलती है। जबकि अकेले धान उत्पादक गोंदिया जिले में इसकी पैदावार 35 लाख क्विंटल है। किसानों द्वारा धान खरीदी शासकीय आधारभूत केंद्रों को बंद कर दिए जाने से हजारों किसान अपना रबी फसल का धान दलालों को कौड़ियों के दाम बेचने मजबूर है। ये किसानों के साथ अन्याय है।

इस मामले को लेकर गोंदिया के विधायक विनोद अग्रवाल की जनता की पार्टी चाबी संगठन ने तहसील अध्यक्ष छत्रपाल तुरकर के नेतृत्व में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्रसिंह तोमर एवं राज्य के अन्न व नागरी आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल को उपविभागीय अधिकारी गोंदिया के माध्यम से पत्र प्रेषित कर, न्याय की गुहार लगाई है।

वर्ष 2021-22 के (रब्बी) फसल में महाराष्ट्र राज्य में केंद्र सरकार ने 15 लाख क्विंटल आधारभुत धान खरेदी करने की मर्यादा निश्चित की है परंतु महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के नागरिक का मुख्य व्यवसाय धान की खेती है और यहाँ धान की खेती की पैदावार बड़े पैमाने पर होती है। जिले के किसानो के फसलो का उत्पादन 35 लाख क्विटंल तक होता है। जिला मार्केटिंग अधिकारी के सर्वेनुसार जिले मे 58120 किसानों की संख्या है, जिसमे इस वर्ष किसानो द्वारा लगाई गई रबी फसल का क्षेत्र 68715 हे.आर. है और इसकी उत्पादक क्षमता 43 प्रति. हेक्टर की दर्शाई गई है।

विशेष है कि महाराष्ट्र में पिछले वर्ष 53 लाख क्विंटल की धान खरेदी की गई थी। उसके अनुसार इस वर्ष 60 लाख क्विंटल की धान खरेदी की मर्यादा की जानी अपेक्षित है। धान खरीदी की मर्यादा बढ़ाये न जाने पर शासकीय समर्थन मूल्य पर धान खरीदी प्रक्रिया बंद कर दी गई है, जिससे किसान अपना धान कौड़ियों के दाम बेचने मजबूर हैं। इससे उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होकर वे आत्महत्या के लिए प्रवर्त हो रहे है। जनता की पार्टी चाबी संगठन ने कहा, जो खरीदी की मर्यादा केंद्र सरकार द्वारा निश्चित की गई है वो कृषि सर्वेयरों की गलती है, इसका भुगतमान किसान क्यों करें?

निवेदन देने वालो में संगठन के जिलाध्यक्ष भाऊराव ऊके, छत्रपाल तुरकर, जिला परिषद सदस्य अनंदा वाढीवा, दीपा चद्रीकापुरे, ममता वाढवे, वैशाली पंधरे, पंस सभापति मुनेश रहांगडाले, टिटूलाल लिल्हारे, किसान आघाड़ी के जिलाध्यक्ष मोहन गौतम, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष चौताली नागपुरे, शैलजा सोनवाने, रामराज खरे, सुजीत येवले, लखन मेंढे, लखन हरिनखेड़े, कमलेश सोनवाने, चेतन बहेकार, दिलीपसिंग मुंडेले, प्रभाकर ढोमने, मीनाक्षी बारलिंगे, शशि राजू कटरे, जितेश्वरी रहांगडाले, विद्या कटरे, सोनुला बरेले, मंजु डोंगरे, मेहतर पगरवार, ज्ञानचंद जमाइवार, लतिश बिसेन, अरविंद हरड़े, लिमेंद बिसेन, कनीराम तवाड़े, अतुल शरणागत, राधेश्याम शरणागत, अशोक मेश्राम, प्रीतम मेश्राम, सुन्दरलाल नागपुरे, ज्ञानेश्वर राऊत, सुरेश राहंगडाले, होमेन्द्र भंडारकर, दीपक वर्मा, लक्ष्मण चौधरी, गणेश पारधी, योगिप्रसाद धामड़े, नीलकंठ मानकर, आशीष नागपुरे, विक्की बघेले, ओमप्रकाश राहंगडाले, आरजू डोंगरे, मिताराम हरड़े, दिनेश तुरकर आदि सहित सैकड़ों किसानों का समावेश रहा।

# जलसंकट से निपटने मजिप्रा ने वैनगंगा नदी पर बनाया बांध

## डांगोरली घाट से नियमित हो रही शहरवासियों को जलापूर्ति

बुलंद गोंदिया - भीषण गर्मी के चलते बढते तापमान से जिले के नदी, तालाबों का जलस्तर घटने से अधिकांश अधिवास क्षेत्रों में जलसंकट की स्थिति निर्माण हो गई थी। शहर के अनेक इलाकों में नियमित जलापूर्ति नहीं होने से प्रभावित नजर आए। घटते जलस्तर को संग्रहित करने तथा वर्तमान स्थिति से निपटने के लिए महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभाग द्वारा तहसील के डांगुर्लीघाट से सटे वैनगंगा नदी पर बांध बनाया गया है। इस संदर्भ में विभाग ने बताया कि बांध को बनाने के लिए प्लास्टिक की बोरी और रेती का उपयोग किया गया है। जिसे मजदूरों की मदद से पूरा किया जा चुका है। बताया जा रहा है कि बांध को लाखों रुपये की लागत से तैयार किया गया है। वहीं बांध का काम पूरा होने के बाद पिछले दो दिनों से शहरवासियों को नियमित जलापूर्ति की जा रही है।

यहां बता दे कि शासन की महत्वाकांक्षी जलापूर्ति योजना को महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभाग द्वारा क्रियान्वित किया गया है। शहर में नगर परिषद क्षेत्र के अधिवास क्षेत्रों में करोडो की लागत से मिट्टी में दफन नई पाईपलाईन बिछायी गई है। शासन की जलापूर्ति योजना का लाभ करीब 23 हजार से अधिक कनेक्शनधारक उठा रहे है। कनेक्शनधारकों को तहसील के डांगुर्लीघाट से सुबह और शाम दो समय विभाग द्वारा नियमित शुध्द जलापूर्ति की जा रही है। बताया जाता है कि गर्मी के मौसम में घटते जलस्तर की वजह से शहरवासियों को अनियमित जलापूर्ति करने की नौबत आन पडी थी। जिससे शहर के अनेक इलाके प्रभावित नजर आए। इस संदर्भ में विभाग ने बताया कि भीषण गर्मी के चलते दिनोंदिन बढते तापमान की वजह से जिले के नदी, तालाबों सहित तहसील के डांगुर्लीघाट में संग्रहित जल का स्तर घट चुका था। शहरवासियों को नियमित जलापूर्ति करने के लिए विभाग को अनेक परेशानियों से गुजरना पडा। लगातार दो माह तक शहरवासियों को सुबह एक ही समय जलापूर्ति करनी पडी। घटते जलस्तर को बचाने तथा जल को संग्रहित करने के लिए विभाग को डांगुर्लीघाट से सटे वैनगंगा नदी पर बांध बनाना पडा।

बताया जा रहा है कि बांध को प्लास्टिक की बोरी और रेती से करीब 10 लाख रुपये की लागत से तैयार किया गया है। जिसे ग्रामीण क्षेत्रों के मजदूरों की मदद से हाल ही में पूरा किया गया है। पश्चात शहर में निर्माण हो रही जलापूर्ति की समस्या को सुलझाने के लिए विभाग को सुबह और शाम दो समय नियमित जलापूर्ति करनी पडी। पता चला है कि नप क्षेत्र के नए विकसित अधिवास क्षेत्रों में मजिप्रा की जलापूर्ति पाईप लाईन नहीं पहुंची है। उन इलाकों में जलसंकट गरमाया नजर आया। इस संदर्भ में विभाग द्वारा पता चला है कि शहर के विकसित इलाकों में करीब 25 कि.मी. की पाईपलाईन बिछायी जानी है। वर्तमान स्थिति से निपटने के लिए विभाग को अनेक चुनौतियों से गुजरना पडेंगा। उसके बाद ही विकसित इलाकों में निर्माण हो रही जलआपूर्ति की समस्या पर विराम लगेंगा।

### जल संग्रहित करने बनाया बांध

तहसील के डांगुर्लीघाट स्थित जलापूर्ति केंद्र का जलस्तर घटने से शहर में जलापूर्ति की समस्या निर्माण हो रही थी। मानसून आने तक जलस्तर को बचाए रखने तथा जल को संग्रहित करने के लिए विभाग को जलापूर्ति केंद्र से सटे वैनगंगा नदी पर प्लास्टिक की बोरी तथा रेती से बांध बनाना पडा। पश्चात शहर में पूर्व की तरह नियमित जलापूर्ति की जा रही है।

- अविनाश पालथे,
उपविभागीय अभियंता, मजिप्रा गोंदिया

# कृषि पंपों को सौर ऊर्जा के माध्यम से विद्युतीकरण के लिए प्रधानमंत्री कुसुम योजना

### महाकृषि ऊर्जा अभियान से - कृषि में सौर ऊर्जा जोड़ें

बुलंद गोंदिया राज्य सरकार ने समय-समय पर गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए प्रोत्साहन नीतियों की घोषणा की है। तदनुसार, राज्य सरकार पिछले कुछ वर्षों से किसानों के कृषि पंप बिजली कनेक्शनों को सौर ऊर्जा के माध्यम से स्व-वित्तपोषण के साथ-साथ केंद्र सरकार के वित्त पोषण से विद्युतीकृत करने के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू कर रही है। इसके तहत महाराष्ट्र सरकार ने देश भर में केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान अभियान (पीएम-कुसुम) को गति देने का फैसला किया है।

राज्य सरकार ने सरकार द्वारा स्वीकृत कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति-2020 के अनुसार सभी किसानों को विश्वसनीय, सस्ती और दिन-प्रतिदिन बिजली आपूर्ति प्रदान करने का निर्णय लिया है। राज्य में सौर ऊर्जा के माध्यम से कृषि पंप बिजली कनेक्शनों को विद्युतीकृत करने के लिए महाकृषि ऊर्जा अभियान की घोषणा की गई है। राज्य मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत अपरंपरागत ऊर्जा उत्पादन नीति-2020 के तहत अगले 5 वर्षों में 1 लाख प्रति वर्ष की दर से 5 लाख गैर पारेषण सौर कृषि पंप स्थापित करने की स्वीकृति दी गई है। यह योजना राज्य के 34 ग्रामीण जिलों में लागू की जाएगी। यह अभियान राज्य में राज्य नोडल एजेंसी (महाराष्ट्र ऊर्जा विकास एजेंसी-मौरजा) के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है।

किसानों को दिन में सिंचाई करना संभव हो और राज्य सरकार के पारंपरिक तरीके से कृषि पंपों के कनेक्शन की लागत और राज्य सरकार द्वारा दी जानेवाली सब्सिडी में बचत का उद्देश्य प्राप्त करना चाहिए। इसके लिए जिस राज्य में परंपरागत तरीके से बिजली उपलब्ध नहीं है, वहां के किसानों को गैर पारेषण सौर कृषि पंप उपलब्ध कराये जायेंगे। इस योजना के लिए केंद्र सरकार की ओर से 30 प्रतिशत वित्तीय सहायता उपलब्ध है। सामान्य वर्ग के हितग्राहियों का अंश 10 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों का अंश 5 प्रतिशत तथा शेष 60 प्रतिशत - 65 प्रतिशत अंश राज्य सरकार के पास होगा।

पीएम-कुसुम योजना को लागू करने के लिए निर्धारित प्रारुप में आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर अलग ऑनलाइन पोर्टल पर महौर्जा के माध्यम से आवेदन करें। सौर कृषि पंपों के लिए आपूर्तिकर्ता के साथ 5 साल के लिए एक व्यापक रखरखाव और मरम्मत समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं और शिकायत पंजीकरण के लिए एक टोल फ्री नंबर उपलब्ध है। सोलर कृषि पंप लग जाने के बाद इसे संबंधित लाभार्थियों को हस्तांतरित किया जाएगा। तब यह संबंधित लाभार्थी की जिम्मेदारी होगी कि वह अपनी दिन-प्रतिदिन की सुरक्षा सुनिश्चित करे। पीएम-कुसुम योजना में भाग लेने के लिए https://kusum-mahaurja.com/solar/beneficiary/register/Kusum&Yojana&Component&B पर जाएं।

वर्तमान में पीएम-कुसुम योजना के तहत 52750 लाभार्थियों की पहचान की गई है और इनमें से 35578 पात्र लाभार्थियों को लाभार्थी के हिस्से का भुगतान करने के लिए एसएमएस भेजा गया था। इसमें से 27026 हितग्राहियों ने लाभार्थी अंश जमा कर दिया है। 18357 स्थानों पर सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है और लगभग 4000 सौर कृषि पंप स्थापित किए गए हैं।

पीएम-कुसुम योजना के तहत अहमदनगर, औरंगाबाद, बीड, बुलढाणा, धुले, हिंगोली, जलगांव, जालना, लातूर, नंदुरबार, नासिक, उस्मानाबाद, नांदेड़, परभणी, पुणे, सोलापुर, वाशिम और यवतमाल जिलों में उपरोक्त उद्देश्यों को हासिल किया गया है। इसके अलावा अकोला, अमरावती, भंडारा, चद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया, कोल्हापुर, नागपुर, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सांगली, सतारा, सिंधुदुर्ग, ठाणे और वर्धा जिलों में सौर कृषि पंप उपलब्ध हैं। इस जिले में लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए विभिन्न माध्यमों से प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजना के तहत अवैध व फर्जी वेबसाइट पर महजा पर कार्रवाई की गई। राज्य में इस तरह की अवैध और फर्जी वेबसाइट और सोशल मीडिया के जरिए किसानों को ठगा जा रहा है। लाभार्थी किसान पीएम-कुसुम योजना में भाग लेने के लिए महाऊर्जा की वेबसाइट का उपयोग करें। सरकार के निर्णय राज्य सरकार की वेबसाइट https//maharashtra.gov.in पर उपलब्ध हैं। ऐसी जानकारी ऊर्जा महानिदेशक रविंद्र जगताप ने दी है।

# भाजपा व करियर लांचर अकादमी ने मनाया गया योग दिवस

बुलंद गोंदिया - विश्व योग दिवस के अवसर पर साकेत पब्लिक स्कूल के प्रांगण में भारतीय जनता पार्टी गोंदिया शहर व गोंदिया करियर लांचर अकादमी एवं योग संस्कृति संघ ने संयुक्त रुप से विश्व योग दिवस मनाया। योग प्रशिक्षक ने योग के महत्व को समझाया और प्रतिभागियों ने विभिन्न योग प्रथाओं का अभ्यास किया। भारत योग अभ्यास का मूल देश है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों के कारण, इस दिन को 2015 से संयुक्त राष्ट्र द्वारा योग दिवस के रुप में मनाया जाता है। नियमित योग स्वस्थ और स्वस्थ जीवन जीने का सबसे अच्छा तरीका है और योग जीवन की कुंजी है, प्रशिक्षक ने कहा।

इस अवसर पर भाजपा जिला महासचिव संजय कुलकर्णी,शहर अध्यक्ष सुनील केलंका, जयंत शुक्ला, गोंदिया करियर लांचर अकादमी के अध्यक्ष रवि रामटेकर, कोच अरुण कावड़े, नेहा खंडेलवाल, मिस्ट्रीज क्रिकेट क्लब के नरसिंह गहरवार, अमित झा, जनार्दन कुसराम, हेमंत हुमे, मोहित भलावी, राकेश शिवंनकर, प्रवीण माने, अशोक जयसिंघानी, लालवानी, मनोज पटनायक, अंकित जैन, मनीष पोपट, बाबा बिसेन, सतीश मेश्राम, चांदवानी, चद्रभान तरोने, मिलिंद बागड़े, राकेश अग्रवाल, देव जयसिंघानिया व बड़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद थे।

# मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है योग - शिक्षा अधिकारी कादर शेख

बुलंद गोंदिया - मानव जीवन के साथ-साथ मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए एक मजबूत, स्वस्थ और सुखी जीवन जीने के लिए नियमित रुप से योग करना आवश्यक है। गोंदिया कादर शेख ने योग दिवस का उद्घाटन किया। योग दिवस के अवसर पर आज जिला खेल परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

जिला खेल अधिकारी घनश्याम राठौर ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा है कि योग तन और मन का संयुक्त व्यायाम है। सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का शुभारंभ मुख्य अतिथि के हाथों दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। खेल एवं युवा सेवा निदेशालय, महाराष्ट्र, पुणे के तहत संयुक्त रुप से जिला खेल अधिकारी कार्यालय, जिला खेल परिषद, प्रशासन, नेहरु युवा केंद्र, नेहरु युवा केंद्र, भारत स्काउट गाइड, अखिल भारतीय योग शिक्षक संघ और जिले के विभिन्न संगठन, परिसर मरारटोली गोंदिया में आयोजित किया गया था। सीमा पाटने उप तहसीलदार, श्रुति डोंगरे युवा अधिकारी नेहरु युवा केंद्र, चेतना ब्रम्हणकर, जिला आयोजक गोंदिया भारत स्काउट गाइड, कुंडा निनावे प्रबंधक, भाग्यश्री गाढ़े सीईओ महिला अर्बन बैक गोंदिया मुख्य अतिथि थे। एनएसयूआई के स्टेट स्पोर्ट्स गाइड, धनंजय भारसाकड़े, विशाल ईश्वरकर, विनय डोंगरवार उपस्थित थे।

अथर्व दीपक परमार, ओजस्वी परमार, भार्गव सुनिद्र मेश्राम और माधुरी परमार योग और प्राकृतिक चिकित्सा विशेषज्ञों को प्रमुख अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान योग प्रशिक्षक माधुरी वांनकर (परमार) ने सामान्य प्रोटोकॉल के अनुसार योग का प्रदर्शन दिया गया। कार्यक्रम में औसतन 200 योग प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यक्रम निदेशक ए.बी. मरस्कोले खेल अधिकारी ने आभार व्यक्त किया। एनएसयूआई के स्टेट स्पोर्ट्स गाइड द्वारा माना जाता है। कार्यक्रम की सफलता के लिए शिवचरण चौधरी, विनेश फुंडे, द्वतुराज यादव, नरेद्र कोचे, शेखर बीरनवार, सुमित कुमार सूर्यवंशी, जयश्री भंडारकर ने अथक प्रयास किया।

स्वामित्व, मुद्रक, प्रकाशक व संपादक नवीन माणिकचंद अग्रवाल द्वारा बुलंद गोंदिया साप्ताहिक समाचार पत्र भवानी प्रिंटींग प्रेस, गुरुनानक वार्ड, गोंदिया, ता.जि.गोंदिया से मुद्रित व बुलंद गोंदिया भवन, जगन्नाथ मंदिर के पास गौशाला वार्ड, गोंदिया ४४१६०१, ता.जि.गोंदिया से प्रकाशित। संपादक : संपादक नवीन माणिकचंद अग्रवाल, मो.क्र. ९४०५२४४६६८। (पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिये जिम्मेदार) प्रकाशित किये गये समाचार व लेख से संपादक सहमत है। न्यायालय क्षेत्र गोंदिया।